Faridabad Plot Built Properties in all Sectors
SYNDICATE
ESTATE AGENCY
Ind. Plot no. 11, Sector-15A, Faridabad.
Ph. : (o) 2284588
(R) : 2224288
Spl. In - Residential, Commercial & Industrial

मेहनतकशों का पैग़ाम
Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06/R.N.I. No. 66400/97

ANCHOR ROADLINES
(Regd) SCO - 29, Shoping Centre, Sec. - 11D, FBD.
Daily Parcel Service
For : Noida, Surajpur, Kasna, Ghaziabad, Haridawar, Gurgaon, Manesar, Dharuhera, Bhiwadi, Vice Varsa
24, Hours Service
Phones : 2285044, 2291388

वर्ष 22 अंक 25 सोमवार, फरीदाबाद, 16-30 नवंबर, 2009 फोन : -2410196,9999595632 सहयोग राशि 1 रुपया

नगर निगम में

शिलान्यासों व उद्घाटनों की अपेक्षा ठोस काम की जरूरत

फ़रीदाबाद (म.मो.) जनता को लुभाने एवं बहकाने के लिये लगभग सभी राजनेता शिलान्यासों व उद्घाटनों में ही लगे रहते हैं। राज्य में भजनलाल द्वारा किये गये कुछ शिलान्यास तो आज भी ऐसे हैं जहां एक ईंट तक भी नहीं लगी। संबंधित विभागों के अधिकारियों के लिये भी यह लाभकारी होता है। इस बहाने उन्हें जहां एक ओर राजनेता की चापलूसी करने का अच्छा-खासा मौका मिलता है, वहीं बेरोकटोक खर्च करने के लिये बजट भी ठीक-ठाक मिल जाता है।

नगर निगम के नये-नये बने मंत्री महोदय को इन सब पाखंडों से बच कर ठोस काम की ओर ध्यान देना चाहिए। स्थानीय निवासी होने के नाते शहर की खस्ताहाल सड़कों, सीवरेज, सफ़ाई व्यवस्था, अवैध कब्ज़ों का मंत्री जी को पूरा-पूरा ज्ञान है। निगम कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा की जाने वाली लूट व हरामखोरी से भी वे अपरिचित नहीं हैं। शहर में जब भी किसी विकास कार्य की बात उठती है तो धन एवं संसाधनों की कमी का रोना रोया जाता है।

वास्तव में कमी धन की नहीं है, कमी काम करने और कराने वालों की है। निगम में छोटे-बड़े 80 इंजीनियर आज के दिन मौजूद हैं। लेकिन कोई यह पूछने वाला नहीं है कि इन्होंने सुबह से लेकर शाम तक काम क्या किया है? अधिकांश इंजीनियरों को यही पता नहीं कि इंजीनियरिंग होती क्या है? वे तो केवल

> "जल की समस्या यहां सबसे बड़ी है। एक ओर पीने के पानी की तो दूसरी ओर बरसाती व सीवेज के गंदे पानी की निकासी की। इन दोनों ही समस्याओं के समाधान पर हर वर्ष करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों रहती है। कारण ? कारण सिर्फ़ नालायकी, हरामखोरी व भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा सरकारी अमला। तमाम नियमों, कानूनों व मानवता को त्याग कर सारे शहर का सीवरेज पानी बिना शोधन के ही यमुना नदी, आगरा व गुड़गांव नहर में बहाने से बड़ी नालायकी और क्या हो सकती है?"

इतना जानते हैं कि टेंडर पास होते ही ठेकेदार से हिस्सा वसूलना है, बाकी काम तो ठेकेदार खुद ही कर लेगा। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि अन्यथा एक रुपये में होने वाला काम निगम द्वारा दस रुपये में क्यों कराया जाता है। दूसरे शब्दों में, एक लाख रुपये में बनने वाली सड़क निगम द्वारा दस लाख रुपये में कैसे बनवाई जाती है? और वही सड़क हर तीसरे-चौथे साल क्यों बनाई जाती है? यहां मामला कोई एक सड़क का नहीं है, हर काम का यही हाल है। इंजीनियरों एवं कर्मचारियों की 'योग्यता' को देखते हुए बेझिझक यह कहा जा सकता है कि यदि इन्हें धन के ट्रक भर-भर कर भी दे दिये जायें तो भी कोइ काम इनके बस का नहीं है। इसलिये इनको धन उपलब्ध करवाना रेत में घी डालने से भी बुरा है, क्योंकि ये लोग उस धन को खर्च कर के काम को और भी बिगाड़ देते हैं जैसे कि सेक्टर-7 में कर रखा है।

जल की समस्या यहां सबसे बड़ी है। एक ओर पीने के पानी की तो दूसरी ओर बरसाती व सीवेज के गंदे पानी की निकासी की। इन दोनों ही समस्याओं के समाधान पर हर वर्ष करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों रहती है। कारण? कारण सिर्फ़ नालायकी, हरामखोरी व भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा सरकारी अमला। तमाम नियमों, कानूनों व मानवता को त्याग कर सारे शहर का सीवरेज पानी बिना शोधन के ही यमुना नदी, आगरा व गुड़गांव नहर में बहाने से बड़ी नालायकी और क्या हो सकती है? जबकि यमुना एक्शन प्लान के तहत सीवेज शोधन के नाम पर अरबों रुपया फूंका जा चुका है।

इंजीनियरिंग के अलावा बाकी अमला भी कोई कम नहीं है, जिसका जहां दाव लगता है, निगम को खाने में जुटा है। एक विरमानी है जो सेवानिवृत होने के बावजूद भी निगम से निकलने को तैयार नहीं है।

शेष पेज 2 पर

श्रम विभाग को भ्रष्टाचारमुक्त कर पायेंगे मंत्री जी?

फ़रीदाबाद (म.मो.) औद्योगिक नगरी होने के नाते श्रम विभाग का अधिक जमावड़ा इसी शहर में है। यह रहस्य भी अब रहस्य नहीं रह गया है कि यहां तैनात होने के लिये तथा लगातार बने रहने के लिए लगभग सभी अधिकारी लूट के माल में से प्रत्येक मंत्री को मंथली देते आये हैं। जो इक्का-दुक्का ईमानदार अधिकारी बिना दिये-लिये यहां तैनात भी हो जाये तो उसका यहां रहना दूभर कर दिया जाता है। मंत्री की मंथली के अलावा उसकी अन्य कार-बिगार आदि भी इन अधिकारियों को भुगतनी पड़ती है। जाहिर है, यह सब वे अपने वेतन से तो करने से रहे। इसके लिये उन्हें फ़ैक्टरी मालिकान पर निर्भर रहना होता है। जब मालिकान इनको पैसा देंगे तो बदले में इन्हें भी मालिकान की गुंडागर्दी एवं गैरकानूनी मज़दूर विरोधी कार्यों की अनदेखी करनी पड़ेगी। इन हालात में, मज़दूर हितों की रक्षा करने वाला श्रम विभाग उद्योगपतियों की अधिक रक्षा करता है। ऐसे में श्रमिक असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक है। और जब असंतोष बढ़ेगा तो वह सब कुछ भी होगा जो नहीं होना चाहिए। नव नियुक्त श्रम मंत्री से फ़रीदाबाद के श्रमिक अपेक्षा तो कर ही सकते हैं कि वे श्रम विभाग से मंथली नहीं उगाहेंगे। ईमानदार और कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे और जो अधिकारी हरामखोरी व भ्रष्टाचार को त्यागने में फ़िर भी असमर्थ हैं, उनको पूरी सख्ती एवं बिना भेदभाव के निपटायेंगे। श्रम मंत्री होने के नाते मंत्री जी के पास एक ऐसा हथियार है जिससे वे बिना कोई चवन्नी खर्चे भी श्रमिकों की भलाई ले सकते हैं। शहर के दो ईएसआई अस्पताल तथा दर्जन भर डिसपेंसरियां भी श्रम मंत्री के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इनमें धन की कतई कोई कमी नहीं है, कमी है तो केवल उचित प्रबंधन की। मौजूदा कुप्रबंधन के चलते ईएसआई की स्वास्थ्य सेवायें मज़दूरों को सुख की अपेक्षा दुख अधिक दे रही हैं। यदि मंत्री महोदय इस ओर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो इनकी तस्वीर ही बदल सकती है।

> "शहर के दो ईएसआई अस्पताल तथा दर्जन भर डिसपेंसरियां भी श्रम मंत्री के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इनमें धन की कतई कोई कमी नहीं है, कमी है तो केवल उचित प्रबंधन की। मौजूदा कुप्रबंधन के चलते ईएसआई की स्वास्थ्य सेवायें मज़दूरों को सुख की अपेक्षा दुख अधिक दे रही हैं।"

क्या जनता की आशाओं पर खरा उतर पायेंगें महेन्द्र प्रताप ?

फ़रीदाबाद (म.मो.) मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के मंत्रिमंडल में एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जिसको जनता से सीधे तौर पर जुड़ने के लिये इतने विभागों के रूप में अवसर उपलब्ध हों। इस औद्योगिक शहर में जहां तीन लाख से अधिक औद्योगिक मज़दूर रहते हैं जिनसे जुड़ने के लिए मंत्री जी के पास श्रम विभाग है। जनता को राशन देने के लिये राशन विभाग उनके पास है। उद्योग-धंधों को चलाने या उजाड़ने के लिए उनके पास उद्योग विभाग है। जिस किसी का उपरोक्त तीनों से ही वास्ता न पड़ता हो तो उसका वास्ता नगर निगम से तो अवश्य ही पड़ेगा; और इन सब से जिसका वास्ता न पड़ता हो तो उसका बिजली विभाग से तो पड़ेगा ही पड़ेगा।

ये सभी विभाग ऐसे हैं, जिनसे वास्ता पड़ने पर लगभग हर आदमी रोता है। इनमें कार्यरत नीचे से लेकर ऊपर तक का हर कर्मचारी व अधिकारी अपने निकम्मेपन व भ्रष्टाचार का परिचय देता मिलता है। जब कभी भी सरकार बदलती है अथवा महकमों के मंत्री बदलते हैं तो जन साधारण में राहत पाने की एक उम्मीद-सी जगती है। लेकिन यह उम्मीद थोड़े दिन बाद मर जाती है। महकमों के अफ़सर बदलते हैं। एक लुटेरे की जगह दूसरा लुटेरा आ बैठता है। जनता की परेशानी वहीं की वहीं रहती है। दरअसल इसके मूल में है व्यापक भ्रष्टाचार। लुटेरे अफ़सर भी लूट के माल में से राजनीतिज्ञों को गाहे-ब-गाहे समयानुसार माल-पानी देते रहते हैं। इनके भारी-भरकम चुनाव खर्चों में भी ये लोग़ हिस्सा बंटाते हैं तो जाहिर है मौका मिलने पर राजनीतिज्ञ भी अपने सेवादारों को लूट के अवसर उपलब्ध कराते रहते हैं।

कुछ अफ़सर और कर्मचारी तो इतने कुशल कलाकार होते हैं कि कोई सरकार हो और चाहे कोई मंत्री हो, वे अपनी चापलूसी व जी-हजूरी से सब को काबू रखने में माहिर होते हैं। इस श्रेणी के लोग़ सबसे अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये ही लोग़ सबसे पहले निष्ठा बदलते हैं। जो भी मंत्री इनके चंगुल में फ़ंसा, समझो कि उसका बंटाढार हुआ, क्योंकि ये लोग़ मंत्री को घुमाने में इतने माहिर होते हैं कि बेचारा मंत्री इधर-उधर की कुछ सोचने के लायक रहता ही नहीं।

> "दबाव में आये राजनेता को अक्सर यह ग़लतफ़हमी होती है कि उक्त भ्रष्ट एवं निकम्मे कर्मचारी को बचाने से उसके वोट बैंक में वृद्धि होती है, जबकि होता इसके विपरीत है। भ्रष्ट कर्मचारी के दो-चार वोट ही होते हैंजबकि उसकी जगह परेशान होने वाली जनता के हज़ारों वोट होते हैं जो प्रायः खुल कर तुरंत ही नहीं बोल पाते, लेकिन मन में गांठ तो बांध ही लेते हैं।"

इन परिस्थितियों और चुनौतियों के मद्देनज़र क्या महेन्द्र प्रताप जनता की जगी उम्मीदों पर खरा उतर पायेंगे? क्या उनके नाम पर वसूली करने वाला कोई नागपाल तो यहां पैदा नहीं हो जायेगा? इसके अलावा मंत्री जी को जनहित तथा कर्मचारी हित के अंतर को भी समझना होगा। जो कर्मचारी अथवा अधिकारी जनता के पैसे से जनता की सेवा करने के लिये तैनात है, वह यदि सेवा के बदले जनता को ही खाने लगे उसके प्रति मंत्री जी यदि सख्त रुख नहीं अपनाते हैं तो जनहित तो खतरे में पड़ेगा ही पड़ेगा। अक्सर होता यह है कि जनता को खाने वाले अधिकारी-कर्मचारी जब फंसने लगते हैं तो वे जाति, बिरादरी, रिश्तेदारी आदि के बल पर दबाव बना कर बच निकलते हैं जिससे पूरे महकमे में का माहौल बिगड़ जाता है तथा भ्रष्टाचार व निकम्मेपन को बढ़ावा मिलता है।

दबाव में आये राजनेता को अक्सर यह ग़लतफ़हमी होती है कि उक्त भ्रष्ट एवं निकम्मे कर्मचारी को बचाने से उसके वोट बैंक में वृद्धि होती है, जबकि होता इसके विपरीत है। भ्रष्ट कर्मचारी के दो-चार वोट ही होते हैंजबकि उसकी जगह परेशान होने वाली जनता के हज़ारों वोट होते हैं जो प्रायः खुल कर तुरंत ही नहीं बोल पाते, लेकिन मन में गांठ तो बांध ही लेते हैं।

महेन्द्र प्रताप ने बड़खल जैसे पंजाबी बहुल क्षेत्र से जीत कर जातिगकत राजनीति करने वालों को भी करारा झटका दिया है। इसलिये उन पर अब यह बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वे अपने रोमर्रा के कार्यकलापों में जातिगत भावनाओं से ऊपर उठ कर कार्य करेंगे। वैसे यह काम इतना सरल तो नहीं है, परंतु आशा तो की ही जानी चाहिये।